भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1487

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

ज़हीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी

1487. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेलंगाना सरकार ने राज्य में ज़हीराबाद औद्योगिक स्मार्ट सिटी के विकास के लिए केन्द्र सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है और स्मार्ट सिटी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, मुख्य रूप से जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति नेटवर्क और अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और कार्यान्वयन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा अनुमोदित 596.61 करोड़ रुपये तुरंत जारी करने का भी अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की स्थिति के अनुसार कितनी धनराशि जारी की गई है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): तेलंगाना सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत हैदराबाद-नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर (एचएनआईसी) के एक भाग के रूप में ज़हीराबाद नोड के विकास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे भारत सरकार ने दिनांक 28 अगस्त, 2024 को अनुमोदन प्रदान किया था।

यह परियोजना सांगारेड्डी जिले में स्थित है और इसका एक्टिवेशन एरिया 3,245 एकड़ है जिसकी कुल परियोजना लागत 2,360 करोड़ रुपए है। जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति नेटवर्क और अन्य सुविधाओं सहित आंतरिक मुख्य अवसंरचना सुविधाओं का विकास करने के लिए भारत सरकार द्वारा अंशदान (राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास और कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी) के माध्यम से) में 596 करोड़ रुपए इक्विटी और 655 करोड़ रुपए

ऋण के रूप में अनुमोदित किए गए हैं। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए "एनआईसीडीआईटी ज़हीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी लिमिटेड" नामक एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का निगमन किया गया है।

एसपीवी में एनआईसीडीआईटी के इक्विटी अंशदान का जारी किया जाना, अन्य बातों के साथ-साथ खसरा संख्या, भूमि मानचित्र और तेलंगाना राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड (टीजीआईआईसी) द्वारा एनआईसीडीसी को भूमि मूल्यांकन सहित भूमि संबंधी विवरण प्रस्तुत किए जाने पर निर्भर है।

*****